अण्डमान निकोबार द्वीप समाचार

रजि.न.34300/80 | संख्या 03 | श्री विजय पुरम, | शनिवार, 03 जनवरी 2026 | web: dt.andamannicobar.gov.in | 2.00 रूपए

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दौरे पर पहुँचे

आज प्रमुख विकास परियोजनाओं का उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह आज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के दौरे पर पहुँचे। वीर सावरकर अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा, श्री विजय पुरम पर उनके आगमन पर एडमिरल डी. के. जोशी, पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (अ.प्रा.), माननीय उप राज्यपाल, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह एवं उपाध्यक्ष, द्वीप विकास एजेंसी द्वारा उनका स्वागत किया गया। इस अवसर पर श्री बिष्णु पद राय, अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय सांसद, डॉ. चंद्र भूषण कुमार (भा.प्र.से.), मुख्य सचिव, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन श्री हरगोबिंदर सिंह ढालीवाल (भा.पु.से.), पुलिस महानिदेशक, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी, जनप्रतिनिधि एवं अन्य गणमान्य व्यक्ति उपस्थित थे।

माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह कल (3 जनवरी, 2026) प्रदर्शिनी मैदान में 'नए आपराधिक कानूनों' पर आधारित प्रदर्शनी का उद्घाटन करेंगे तथा उसका अवलोकन भी करेंगे। इसके अतिरिक्त, माननीय मंत्री 3 जनवरी को शाम 3.30 बजे नेताजी स्टेडियम में आयोजित एक कार्यक्रम में द्वीपसमूह की कई महत्वपूर्ण विकास परियोजनाओं का इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उद्घाटन एवं शिलान्यास करेंगे।

उद्घाटन की जाने वाली परियोजनाओं में गाराचरामा ज़िला अस्पताल (चरण–1), श्री विजय पुरम में फॉरेंसिक विज्ञान प्रयोगशाला, श्री विजय पुरम में एकीकृत नियंत्रण एवं कमान केंद्र सहित कई अन्य विकास परियोजनाएँ शामिल हैं। वहीं श्री विजय पुरम में क्रिटिकल केयर यूनिट तथा ग्रेट निकोबार में प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना की परियोजनाओं के लिए शिलान्यास किया जाएगा। उद्घाटन एवं शिलान्यास समारोह के पश्चात माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह जनसभा को संबोधित करेंगे। इस कार्यक्रम में अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के माननीय उप राज्यपाल, माननीय सांसद एवं अन्य गणमान्य व्यक्तियों की गरिमामयी उपस्थिति रहेगी।

गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सीएफएसएल–एनएफएसयू पर बैठक आज

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति की सीएफएसएल–एनएफएसयू पर बैठक कल (3 जनवरी) को सुबह 11 बजे सी प्रिंसेस, वंडूर, श्री विजय पुरम में आयोजित की जाएगी। इस बैठक की अध्यक्षता माननीय केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह करेंगे।

इस बीच, गृह मंत्रालय की परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्य आज अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के तीन दिवसीय दौरे पर पहुँचे। आगमन के तुरंत बाद परामर्शदात्री समिति के माननीय सदस्यों ने राष्ट्रीय स्मारक सेल्यूलर जेल का भ्रमण किया तथा लाइट एंड साउंड शो का अवलोकन किया।

मत्स्य विभाग ने क्षेत्रीय महत्व के आधार पर स्वदेशी प्रजातियों के उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए, कुल 34 क्लस्टर में अण्डमान तथा निकोबार भी शामिल

नई दिल्ली, 2 जनवरी। (प.सू.का.)

हिमालयी नदियों से लेकर हिंद महासागर के तटीय जल तक फैले भारत के विविध जलीय इको–सिस्टम में स्वदेशी मछली प्रजातियों का भंडार है। यह देश के पारिस्थितिक संतुलन और सांस्कृतिक विरासत का अभिन्न अंग हैं। इन स्वदेशी प्रजातियों का संवर्धन न केवल मत्स्य पालन की स्थिरता के लिए बल्कि खाद्य सुरक्षा बढ़ाने, स्थानीय अर्थव्यवस्थाओं को समर्थन देने और जैव विविधता के संरक्षण के लिए भी आवश्यक है। देश में मछली उत्पादों की बढ़ती मांग को पूरा करने और पर्यावरणीय चुनौतियों से निपटने के प्रयासों के बीच, देशी मछली प्रजातियों का रणनीतिक संवर्धन देश की समृद्ध जलीय विरासत को संरक्षित करते हुए इन लक्ष्यों को प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करता है।

स्थानीय या देशी प्रजातियां वे हैं जो विशिष्ट भौगोलिक क्षेत्रों और जलीय वातावरणों के अनुकूल विकसित और अनुकूलित हुई हैं। भारत में, इन प्रजातियों में मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री मछलियों की एक विस्तृत विविधता शामिल है। इनमें से प्रत्येक की अपनी अनूठी पारिस्थितिक भूमिका और आर्थिक महत्व है। 2800 से अधिक स्थानीय मछली और शंख प्रजातियों की पहचान की गई है। इनमें से 917 प्रजातियाँ मीठे पानी से, 394 प्रजातियां खारे पानी से और 1548 प्रजातियां समुद्री हैं (स्रोतः आईसीएआर–एनबीएफजीआर)।

इन वर्षों में देश ने व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण 80 से अधिक मछली/शंख प्रजातियों के लिए प्रजनन और बीज उत्पादन प्रौद्योगिकियां विकसित की हैं। हालांकि, देश के मत्स्य पालन उत्पादन में मुख्य योगदान कुछ चुनिंदा प्रजातियों का ही है। तीन प्रमुख कार्प प्रजातियां, रोहू, कतला और मृगाल तथा विशाल मीठे पानी का झींगा, भारतीय मीठे पानी के मत्स्य पालन का आधार हैं। परिणामस्वरूप, देश में मीठे पानी के मत्स्य पालन से उत्पादित 19.50 मिलियन टन मछली में से तीन–चौथाई से अधिक भारतीय प्रमुख कार्प प्रजातियों का योगदान है। खारे पानी के मत्स्य पालन में, वर्तमान उत्पादन का अधिकांश हिस्सा एक ही विदेशी झींगा प्रजाति (पेनायस वन्नामेई) का है, जबकि स्वदेशी ब्लैक टाइगर झींगा (पेनायस मॉनडॉन) का योगदान बहुत कम है । देश में समुद्री मत्स्य पालन अभी भी प्रारंभिक अवस्था में है।

शेष पृष्ठ 4 पर

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अण्डमान तथा निकोबार कमान का दौरा

सभी रैंकों से उभरती चुनौतियों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) जनरल अनिल चौहान, पीवीएसएम, यूवाईएसएम, एवीएसएम, एसएम, वीएसएम, एडीसी ने अण्डमान तथा निकोबार कमान की परिचालन भूमिका की समीक्षा, अवसंरचना विकास की प्रगति का आकलन तथा सामरिक रूप से महत्वपूर्ण द्वीपीय क्षेत्रों में त्रि–सेवाओं के बीच समन्वय को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 2 जनवरी को अण्डमान तथा निकोबार कमान के दो दिवसीय दौरे पर आगमन किया।

दौरे के तहत सीडीएस सर्वप्रथम कार निकोबार स्थित वायु सेना स्टेशन पहुँचे, जो अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का एक प्रमुख परिचालन हवाई अड्डा है। उनका स्वागत वाइस एडमिरल अजय कोच्चर, एवीएसएम, एनएम, कमांडर–इन–चीफ, अण्डमान तथा निकोबार कमान तथा एयर कमोडोर कमल चड्ढा, एयर ऑफिसर कमांडिंग, एयर फोर्स कंपोनेंट हेडक्वार्टर द्वारा किया गया।

वायु सेना स्टेशन, कार निकोबार में सीडीएस ने नव–पुनर्विकसित रनवे का उद्घाटन किया, जिसके साथ उन्नत सहायक अवसंरचना भी शामिल है। यह द्वीपों में महत्वपूर्ण विमानन अवसंरचना के सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक प्रमुख उपलब्धि है। उन्नत रनवे से लड़ाकू विमानों सहित हवाई अभियानों में उल्लेखनीय वृद्धि होगी तथा अग्रिम पंक्ति के युद्धक संसाधनों के आगमन, ठहराव और सतत संचालन की क्षमता में सुधार होगा।

दौरे के दौरान सीडीएस ने अतिरिक्त विमानन ईंधन भंडारण सुविधा का भी उद्घाटन किया। इस संवर्धन से विमानों की परिचालन सीमा और धीरज में वृद्धि होगी, जिससे त्वरित तैनाती, सतत हवाई उपस्थिति और मिशन तत्परता में सुधार संभव होगा।

उन्नत अवसंरचना क्षेत्रीय संपर्क योजना (आरसीएस–उड़ान) को भी समर्थन प्रदान करेगी, जिससे दूरस्थ द्वीपीय क्षेत्रों तक नागरिक हवाई संपर्क में सुधार होगा। यह भूकंप एवं सुनामी संभावित क्षेत्र तथा आसपास के क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदाओं और आपात स्थितियों के दौरान संसाधनों की त्वरित तैनाती को सक्षम बनाकर मानवीय सहायता एवं आपदा राहत (एचएडीआर) क्षमता को भी सुदृढ़ करेगी।

दौरे के दौरान सीडीएस ने अण्डमान तथा निकोबार कमान की परिचालन भूमिका, चल रहे अवसंरचना विकास कार्यों तथा थल सेना, नौसेना, वायु सेना और तटरक्षक बल के बीच संयुक्तता के स्तर की समीक्षा की। उन्होंने क्षेत्र में निगरानी, प्रतिरोधक क्षमता और त्वरित प्रतिक्रिया को सशक्त बनाने हेतु निर्बाध समन्वय के महत्व पर बल दिया।

सीडीएस ने अण्डमान तथा निकोबार कमान के कर्मियों को संबोधित करते हुए उनकी पेशेवर दक्षता, उच्च स्तर की तत्परता और द्वीपीय क्षेत्रों में राष्ट्रीय हितों की सुरक्षा के प्रति अटूट प्रतिबद्धता

शेष पृष्ठ 4 पर

द्वीप पर्यटन महोत्सव के दौरान आयोजित 'स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता' के परिणाम

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

स्वास्थ्य सेवा निदेशालय, अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन ने संघ शासित प्रदेश स्वास्थ्य मिशन (यूटीएचएम) के सहयोग से 30 दिसंबर, 2025 को प्रदर्शिनी मैदान में द्वीप पर्यटन महोत्सव–2025 के अवसर पर 'स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता' का आयोजन किया। यह प्रतियोगिता स्वास्थ्य एवं खुशहाली का उत्सव रही, जिसमें प्रारंभिक बाल्यावस्था के स्वास्थ्य एवं पोषण के महत्व को उजागर किया गया।

प्रदर्शिनी मैदान में आयोजित स्वस्थ शिशु प्रतियोगिता के विजेताओं के नाम निम्नलिखित हैं:		
श्रेणी: 6 माह से 1 वर्ष		
नाम	पिता का नाम	स्थान
शनाया ज़मीर	ज़मीर अहमद	पहला
आरव एस. नायर	आनंद के. विजयन	दूसरा
रिद्धिशा	राजेश कुमार मंडल	तीसरा
टी. वंशित	टी. वेंकटेश्वर राव	सांत्वना
श्रेणी: 1 वर्ष से 3 वर्ष		
नाम	पिता का नाम	स्थान
अनिका पांडे	श्रीकांत पांडे	पहला
के. सान्वी	बी. काली दास	दूसरा
सान्विका सिंह	संकेत सिंह	तीसरा
जीविका यादव	रमेश यादव	सांत्वना
श्रेणी: 3 वर्ष से 5 वर्ष		
नाम	पिता का नाम	स्थान
अदिति सिंह	दिलीप कुमार सिंह	पहला
आध्या एम. सिद्धांत	जे. सिद्धांत	दूसरा
बी. थानवी	बी. कालिदास	तीसरा
कियारा बिस्वास	बिष्णुदास बिस्वास	सांत्वना

दूरदर्शन केन्द्र द्वारा विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ का लाइव प्रसारण आज

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

दूरदर्शन केंद्र, श्री विजय पुरम द्वारा माननीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह द्वारा नेताजी स्टेडियम, श्री विजय पुरम से विभिन्न परियोजनाओं के शुभारंभ का लाइव प्रसारण शाम 3.40 बजे से कार्यक्रम की समाप्ति तक किया जाएगा। प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार यह लाइव प्रसारण दूरदर्शन केंद्र के आधिकारिक यूट्यूब चैनल @ddksrivijayapuram पर भी उपलब्ध रहेगा।

मत्स्य विभाग ने क्षेत्रीय महत्व के आधार पर

पृष्ठ 1 का शेष

देश में मत्स्यपालन विविधीकरण को बढ़ावा देने के लिए, मीठे पानी, खारे पानी और समुद्री वातावरण में मत्स्यपालन के लिए महत्वपूर्ण संभावित स्वदेशी मछली प्रजातियों को प्राथमिकता देना आवश्यक महसूस किया जा रहा है। आर्थिक महत्व और क्षेत्रीय महत्व के आधार पर निम्नलिखित स्वदेशी प्रजातियों को प्राथमिकता दी गई हैरू 1. फ्रिंज्ड–लिप्ड कार्प (लेबियो फ़िम्ब्रिएटस), 2. ऑलिव बार्ब (सिस्टोमस सराना), 3. पेंग्बा (ओस्टियोब्रामा बेलांगेरी), 4. स्ट्राइप्ड मुर्रेल (चन्ना स्ट्रिएटा), 5. पाब्दा (ओमपोक एसपीपी), 6. सिंघी (हेटेरोप्नेस्टेस फॉसिलिस), 7. एशियन सीबास (लेट्स कैल्केरिफ़र), 8. पर्लस्पॉट (एट्रोप्लस सुराटेन्सिस), 9. पोम्पानो (ट्रैकिनोटस एसपीपी.), 10. मड क्रैब (स्काइला एसपीपी.), 11. पेनायस इंडिकस।

ऊपर चयनित प्रजातियां मत्स्यपालन के लिए उत्कृष्ट उम्मीदवार मानी जाती हैं, और इनका प्रजनन, बड़े पैमाने पर बीज उत्पादन की तकनीकें और पालन–पोषण की पद्धतियां पहले से ही उपलब्ध हैं। ये प्रजातियां समुदायों और उनके जलीय वातावरण के बीच गहरे सम्बंध को दर्शाती हैं और सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देती हैं। ये प्रजातियां न केवल सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं, बल्कि स्थानीय समुदायों के भरण–पोषण के लिए भी आवश्यक हैं, क्योंकि स्थानीय और क्षेत्रीय बाजारों में इनका उच्च मूल्य है। ये लाखों लोगों के आहार का एक महत्वपूर्ण हिस्सा हैं और मत्स्यपालन उत्पादन और आय में महत्वपूर्ण योगदान दे सकती हैं।

स्वदेशी मछली प्रजातियों को बढ़ावा देने के लाभों के बारे में अक्सर जागरूकता और तकनीकी ज्ञान की कमी पाई जाती है। यह कमी इन प्रजातियों को मत्स्य पालन प्रणालियों में एकीकृत करने के प्रयासों में बाधा डालती है। इसलिए, हितधारकों को शिक्षित करना और स्वदेशी प्रजातियों के प्रजनन, बीज उत्पादन और विकास प्रक्रियाओं के लाभों और तकनीकों पर प्रशिक्षण प्रदान करना आवश्यक है। भारत मत्स्य प्रबंधन और पर्यावरणीय स्थिरता की जटिलताओं से जूझ रहा है, ऐसे में इन स्वदेशी मछली प्रजातियों को बढ़ावा देना एक आशाजनक मार्ग प्रदान करता है। जलीय संसाधनों के दीर्घकालिक स्वास्थ्य और समृद्धि को सुनिश्चित करने के लिए इन प्रजातियों के अद्वितीय पारिस्थितिक, आर्थिक और सांस्कृतिक मूल्यों का लाभ उठाकर, भारत मत्स्य पालन के लिए अधिक संतुलित और टिकाऊ दृष्टिकोण अपना सकता है।

अंतर्देशीय और जलीय कृषि मिलकर भारत के मछली उत्पादन में 75 प्रतिशत से अधिक का योगदान करते हैं, जो मछली पकड़ने की पारंपरिक प्रणालियों की तुलना में मत्स्य पालन प्रणालियों के प्रभुत्व को दर्शाता है। इसलिए, सरकार का मत्स्य विभाग (डीओएफ) अपनी मौजूदा योजनाओं जैसे प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना (पीएमएमएसवाई), नई उप–योजना प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह–योजना (पीएमएमकेएसवाई) और मत्स्य एवं जलीय कृषि अवसंरचना विकास कोष (एफआईडीएफ) के माध्यम से गुणवत्तापूर्ण और किफायती बीज और चारा की आपूर्ति में अंतर को पाटने और प्रशिक्षण एवं कार्यशालाओं के माध्यम से जनसमुदाय को तकनीकी ज्ञान का प्रसार करने के लिए काम कर रहा है। पीएमएमएसवाई देश में मत्स्य पालन क्षेत्र के विकास और स्थिरता को बढ़ावा देने के लिए बनाई गई एक व्यापक योजना है। इसके प्राथमिक उद्देश्य जलीय कृषि उत्पादकता बढ़ाना, मछुआरों की आजीविका में सुधार करना और जलीय संसाधनों का सतत उपयोग सुनिश्चित करना है। यह योजना, जलीय कृषि का विस्तार, प्रजातियों का विविधीकरण और आनुवंशिक सुधार जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों पर केंद्रित है। ये प्रयास भूमि और जल संसाधनों के उत्पादक उपयोग में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, जो इस क्षेत्र के विकास के लिए आवश्यक हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) अपने विभिन्न अनुसंधान संस्थानों के माध्यम से स्वदेशी मछली प्रजातियों पर व्यापक शोध करता है, इसमें उनकी जीव विज्ञान, प्रजनन संबंधी आदतें, व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण मछली और शंख प्रजातियों के आनुवंशिक सुधार कार्यक्रम और पर्यावास सम्बंधी आवश्यकताओं का अध्ययन शामिल है। आईसीएआर लुप्तप्राय और संकटग्रस्त स्वदेशी मछली प्रजातियों के संरक्षण के लिए पर्यावास संरक्षण, प्रजनन कार्यक्रमों और आनुवंशिक संरक्षण हेतु रणनीतियों का विकास और कार्यान्वयन करके भी सक्रिय रूप से जुड़ा हुआ है।

मत्स्य विभाग ने आईसीएआर के परामर्श से कुछ स्वदेशी प्रजातियों का आनुवंशिक सुधार हेतु चयन किया है और गुणवत्तापूर्ण एवं स्वस्थ बीज उत्पादन के लिए आईसीएआर के मत्स्य संस्थानों को वित्तीय सहायता प्रदान की है। चयनित प्रजातियां हैं: स्कैम्पी, रोहू, कतला, मुर्रेल, पी. इंडिकस, पी. मोनोडॉन और इंडियन पोम्पानो । इसके अतिरिक्त, विभाग ने पीएमएमएमएसवाई के तहत आईसीएआर–केंद्रीय मीठे जल मत्स्य पालन संस्थान (आईसीएआर–सीआईएफए), भुवनेश्वर में मीठे जल मत्स्य पालन प्रजातियों के लिए और आईसीएआर–केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान संस्थान (आईसीएआर–सीएमएफआरआई), मंडपम के क्षेत्रीय केंद्र में समुद्री प्रजातियों के लिए नाभिकीय प्रजनन केंद्र (एनबीसी) की स्थापना को भी मंजूरी दी है।

मत्स्य विभाग ने क्षेत्रीय महत्व के आधार पर स्वदेशी प्रजातियों के उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर अधिसूचित किए हैं। इनका उद्देश्य उत्पादन बढ़ाना, मूल्य श्रृंखला को मजबूत करना, फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और ग्रामीण महिलाओं और युवाओं को रोजगार प्रदान करना है। कुल 34 क्लस्टर अधिसूचित किए गए हैं, जिनमें पूर्वोत्तर राज्यों, जम्मू और कश्मीर, लद्दाख, अण्डमान तथा निकोबार और लक्षद्वीप आदि में उत्पादन और प्रसंस्करण क्लस्टर का विकास शामिल है। स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बनाए गए क्लस्टर इस प्रकार हैं: ओडिशा में स्कैम्पी क्लस्टर, तेलंगाना में मुर्रेल क्लस्टर, त्रिपुरा में पाबदा क्लस्टर, मणिपुर में पेंगबा क्लस्टर, जम्मू और कश्मीर में ट्राउट क्लस्टर, लद्दाख में ट्राउट क्लस्टर, केरल में पर्ल स्पॉट क्लस्टर, कर्नाटक में पिंजरा संस्‌ति के माध्यम से समुद्री स्वदेशी प्रजातियों को बढ़ावा देना, मदुरै में सजावटी मत्स्य पालन क्लस्टर।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का अण्डमान

पृष्ठ 1 का शेष

की सराहना की। एएनसी के विशिष्ट सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए उन्होंने सभी रैंकों से संयुक्तता, अनुकूलनशीलता और परिचालन उत्कृष्टता को निरंतर प्रोत्साहित करने तथा उभरती चुनौतियों के प्रति त्वरित प्रतिक्रिया के लिए सदैव तैयार रहने का आह्वान किया।

कमान मुख्यालय से प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार द्वीपीय क्षेत्रों के सामरिक महत्व को रेखांकित करते हुए सीडीएस ने पुनः दोहराया कि ये पहलें भारत के संप्रभु क्षेत्रीय जल की सुरक्षा और राष्ट्रीय समुद्री हितों के संरक्षण के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। यह दौरा द्वैध–उपयोग रक्षा अवसंरचना के आधुनिकीकरण, परिचालन क्षमताओं के संवर्धन तथा सुरक्षा और विकास को समानांतर रूप से आगे बढ़ाने पर भारत सरकार के निरंतर ध्यान को प्रतिबिंबित करता है।

सार्वजनिक कार्यक्रमों में आमंत्रित अतिथियों एवं आम जनता को सलाह

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

पुलिस अधीक्षक (सुरक्षा) द्वारा जारी विज्ञप्ति में जनवरी, 2026 के प्रथम सप्ताह के दौरान अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह में वीवीआईपी के आगमन एवं उनके द्वारा सार्वजनिक कार्यक्रमों में भाग लेने के मद्देनज़र, पुलिस व्यवस्था की तैयारियों के संदर्भ में यह सूचित किया जाता है कि सुरक्षा की दृष्टि से आमंत्रित अतिथियों एवं आम जनता को सलाह दी जाती है कि वे वीवीआईपी द्वारा भाग लिए जाने वाले कार्यक्रम स्थलों पर माला, गुलदस्ता, पावर बैंक, बैटरी चालित खिलौने, सिक्के, पेजर, कैमरा, दूरबीन, सिगरेट, लाइटर, माचिस, हैंडबैग, छाता, पानी की बोतल, पैकेट, ब्रीफकेस, ट्रांसमीटर, टिफिन बॉक्स, काँच की वस्तुएँ, स्क्रू ड्राइवर आदि जैसे नुकीले/तेजधार वस्तुएँ इत्यादि वस्तुएँ साथ न लाएँ।

आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे के मद्देनज़र यातायात परामर्श

सहायता के लिए ट्रैफिक हेल्पलाइन नम्बर 03192–243812, व्हाट्सएप 9531892228 पर संपर्क करें

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

यह सूचित किया जाता है कि आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के दौरे को ध्यान में रखते हुए तथा वाहनों की सुचारु एवं सुरक्षित आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए, सुव्यवस्थित यातायात व्यवस्था बनाए रखने हेतु कुछ उपाय किए जाएंगे। साथ ही, आम जनता की आवागमन सुविधा के लिए कुछ स्थानों पर वैकल्पिक मार्ग भी उपलब्ध कराए जाएंगे, जिसकी सूचना नीचे अनुसार दी जाएगी।

03.01.2026 (शनिवार)		
मुख्य मार्ग	वैकल्पिक मार्ग	समय
नेताजी स्टेडियम, अग्निशमन मुख्यालय, सचिवालय, डॉलीगंज, भातूबस्ती, गाराचरामा, सीपीघाट, धानीखाड़ी	आरजीटी रोड–हवाघर जंक्शन नया गांव–चक्करगांव–कार्बिन चौक जंक्शन,–भातूबस्ती (इसके विपरीत)	दोपहर 2.30 बजे से शाम 5.30 बजे तक

हवाई अड्डे की यात्रा, परीक्षा में सम्मिलित होने, चिकित्सीय आवश्यकताओं अथवा किसी भी आपात स्थिति में यात्रियों से अनुरोध है कि वे ट्रैफिक कंट्रोल रूम से संपर्क करें या व्हाट्सएप पर संदेश भेजें। ऐसे आवागमन के लिए अण्डमान तथा निकोबार ट्रैफिक पुलिस द्वारा प्राथमिकता के आधार पर सुविधा प्रदान की जाएगी। किसी भी स्थान पर सड़क अवरोध या मार्ग बंद नहीं किया जाएगा। यातायात के प्रवाह को नियंत्रित करने, जाम की स्थिति से बचने तथा शहर भर में वाहनों की सुचारु आवाजाही बनाए रखने के लिए वैकल्पिक यातायात मार्ग योजना लागू की गई है। यातायात के पुलिस अधीक्षक से प्राप्त विज्ञप्ति में यात्रियों को सलाह दी गई है कि वे अपनी यात्रा की अग्रिम योजना बनाएं। ट्रैफिक पुलिस कर्मी सुगम एवं सुरक्षित आवागमन में सहायता प्रदान करेंगे।

वीआईपी दौरे को ध्यान में रखते हुए निषेधात्मक आदेश जारी

ड्रोन, पैरा–ग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग तथा हवाई गतिविधियों पर प्रतिबंध

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

दक्षिण अण्डमान ज़िले के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने पत्र संख्या एसएसपी (डी) एसए/वीआईपी/2025/5383 दिनांक 22 दिसंबर, 2025 के माध्यम से 2 जनवरी, 2026 से 4 जनवरी, 2026 तक अण्डमान तथा निकोबार द्वीपसमूह की वीआईपी यात्रा के संबंध में अनुरोध प्रस्तुत किया है। वीआईपी दक्षिण अण्डमान ज़िले में विभिन्न स्थानों का दौरा करने वाले है, मौजूदा सुरक्षा चिंताओं और हालिया आतंकवादी खतरों के कारण कड़े सुरक्षा उपायों की आवश्यकता है। ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 के अनुसार सुरक्षा के दृष्टिकोण से अप्रिय घटनाओं को रोकने के लिए एहतियाती उपाय सुनिश्चित करना अनिवार्य है। अतः भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ज़िलाधीश, दक्षिण अण्डमान ज़िला द्वारा निषेधात्मक आदेश जारी किया गया है। जिसके तहत सभी दूर से संचालित विमान प्रणालियों (आरपीए)/ड्रोन के साथ–साथ पैरा–ग्लाइडिंग, पैराशूट जंपिंग या इसी तरह की हवाई गतिविधियों का उड़ान, संचालन या उपयोग वीर सावरकर इंटरनेशनल (वीएसआई) हवाई अड्डा, आईटीएफ ग्राउंड, डीब्राइट, लोक निवास, वंडूर, चिड़ियाटापू और नेताजी स्टेडियम क्षेत्र आदि स्थानों पर और उसके आसपास निषिद्ध है। दक्षिण अण्डमान ज़िले के ज़िलाधीश द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह निषेध 4 जनवरी, 2026 तक लागू रहेगा, ड्रोन नियम, 2021 और ड्रोन (संशोधन) नियम, 2022 के प्रावधानों के अनुरूप सख्ती से लागू किया जाएगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाला कोई भी व्यक्ति भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस), 2023 की धारा 223 के साथ–साथ विमान अधिनियम, 1934, ड्रोन नियमों या लागू किसी अन्य प्रासंगिक वैधानिक प्रावधानों सहित कानून के अन्य लागू प्रावधानों के तहत सज़ा के लिए उत्तरदायी होगा।

'डाइट' द्वारा 40 समुदाय सदस्यों के लिए बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण आयोजित

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

डॉ. एस. राधाकृष्णन ज़िला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान (डाइट), गाराचरामा, श्री विजय पुरम ने समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत सीआरसी गाराचरामा एवं सीआरसी स्कूल लाइन के एसएमसी, एसएमडीसी, पीटीए से संबंधित 40 समुदाय सदस्यों के लिए 30 दिवसीय बुनियादी कंप्यूटर प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य डिजिटल साक्षरता, व्यावसायिक कौशल और सामुदायिक सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन मुख्य अतिथि श्रीमती ज्योति, सीआरसी समन्वयक एवं प्रधानाचार्या, पीएम श्री राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, गाराचरामा द्वारा किया गया। प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए उन्होंने वर्तमान समय में डिजिटल साक्षरता को एक आवश्यक जीवन कौशल बताया। इस अवसर पर कार्यक्रम समन्वयक श्रीमती आराधना यादव, प्रवक्ता, शैक्षिक प्रौद्योगिकी, 'डाइट' ने बताया कि कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रतिभागियों को दैनिक उपयोग के लिए आवश्यक कंप्यूटर कौशल से लैस करना है। इनमें बुनियादी कंप्यूटर संचालन, कंप्यूटर हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर की समझ, ऑपरेटिंग सिस्टम का उपयोग, टाइपिंग कौशल, सरल दस्तावेज़ों की तैयारी तथा इंटरनेट का सुरक्षित और ज़िम्मेदार उपयोग शामिल है। यह प्रशिक्षण कार्यक्रम व्यावहारिक सीख पर केंद्रित है और प्रतिभागियों को डिजिटल रूप से आत्मविश्वासी एवं आत्मनिर्भर बनाने का लक्ष्य रखता है। इससे वे अपने परिवारों, विशेषकर विद्यालय जाने वाले बच्चों को डिजिटल शिक्षण गतिविधियों में शैक्षणिक एवं तकनीकी सहायता प्रदान करने में सक्षम होंगे।

प्राप्त विज्ञप्ति के अनुसार इस प्रकार की पहलें समग्र शिक्षा के अंतर्गत 'डाइट', गाराचरामा की समावेशी शिक्षा, आजीवन अधिगम और सामुदायिक सहभागिता के प्रति निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं तथा राष्ट्रीय शिक्षा नीति (एनईपी)–2020 के दृष्टिकोण के अनुरूप समुदाय सदस्यों में व्यावसायिक शिक्षा एवं कौशल विकास को बढ़ावा देकर एक डिजिटल रूप से सशक्त और कुशल समाज के निर्माण में योगदान देती हैं।

स्पॉन उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं जैविक ऑयस्टर मशरूम उत्पादन पर प्रशिक्षण में 20 प्रतिभागी शामिल हुए

श्री विजय पुरम, 2 जनवरी

आईसीएआर–कृषि विज्ञान केंद्र (सीआईएआरआई), दक्षिण अण्डमान द्वारा 29 से 31 दिसंबर, 2025 तक दक्षिण अण्डमान स्थित केवीके परिसर में "स्पॉन उत्पादन प्रौद्योगिकी एवं जैविक ऑयस्टर मशरूम उत्पादन" विषय पर तीन दिवसीय प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम का सफल आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम का उद्देश्य किसानों, ग्रामीण युवाओं तथा उभरते उद्यमियों के तकनीकी ज्ञान और व्यावहारिक कौशल को सुदृढ़ करना था, ताकि द्वीपीय परिस्थितियों के अनुकूल मशरूम उत्पादन एवं स्पॉन उत्पादन को सतत एवं आय–सृजनकारी उद्यम के रूप में प्रोत्साहित किया जा सके। कार्यक्रम का उद्घाटन डॉ. वाई. रामकृष्ण, प्रधान वैज्ञानिक एवं प्रमुख, कृषि विज्ञान केंद्र, श्री विजय पुरम द्वारा किया गया। अपने उद्घाटन संबोधन में डॉ. रामकृष्ण ने प्रतिभागियों को आजीविका के एक

व्यवहार्य विकल्प के रूप में मशरूम उत्पादन अपनाने के लिए प्रेरित किया तथा गुणवत्तापूर्ण उत्पादन और अधिक लाभप्रदता के लिए वैज्ञानिक विधियों के महत्व पर बल दिया। उन्होंने कम निवेश, अल्प उत्पादन चक्र, कृषि अवशेषों के प्रभावी उपयोग तथा उच्च पोषण मूल्य के कारण ऑयस्टर मशरूम उत्पादन की संभावनाओं को रेखांकित किया।

सूचना, प्रचार और पर्यटन निदेशालय द्वारा प्रकाशित तथा प्रबन्धक, राजकीय मुद्रणालय द्वारा मुद्रित, वितरण तथा विज्ञापन के लिए फोन–229465, प्रधान सम्पादक (प्रभारी) पी. कैरल डी. सोणी
e-mail:dweepsamachar@gmail.com

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय, श्री विजय पुरम

प्रेस विज्ञप्ति

F.No. 4-13/2025 - R & E Cell/494 दिनांक 31.12.2025

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 06.11.2025 के रिक्ति सूचना 4–12/2025/आर एंड ई सेल/382 के संदर्भ में संयुक्त स्नातक स्तर की परीक्षा के लिए उम्मीदवारों/आवेदकों को सूचित किया जाता है कि पदों से संबंधित पाठ्यक्रम दिनांक 02.01.2026 से संबंधित पोर्टल https://erecruitment.andamannicobar.gov.in पर उपलब्ध करवाया जाएगा।

ह./–
(एम. वी. रमेशन)
उप सचिव (भर्ती एवं परीक्षा)

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन
सचिवालय, श्री विजय पुरम

प्रेस विज्ञप्ति

F.No. 4-13/2025 - R & E Cell/492 दिनांक 31.12.2025

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के दिनांक 06.11.2025 के रिक्ति सूचना संख्या : 4–12/2025–आर एंड ई सेल/382 के संदर्भ में, संयुक्त स्नातक स्तर परीक्षा के लिए दिनांक 07.01.2026 के प्रातः 11.00 बजे से लेकर 13.01.2026 (रात्रि 12.00 बजे तक) एक सुधार विंडो खोली जा रही है, जिससे आवेदक द्वारा की गई, यदि कोई त्रुटि हो, तो अपने आवेदन में सुधार कर सकते हैं।

इस प्रकार आवेदक वेबसाइट के पोर्टल https://erecruitment.andamannicobar.gov.in में जाकर, यदि कोई त्रुटि हो तो, सुधार कर सकते हैं।

वेबसाइट पर उपलब्ध उम्मीदवारों का आवेदन से संबंधित विवरण अंतिम तिथि, अर्थात 13.01.2026 के मध्य रात्रि के उपरान्त अंतिम माना जाएगा। अतः उम्मीदवारों के हित में सलाह दी जाती है कि ऊपरनिर्दिष्ट समय सीमा के भीतर सावधानीपूर्वक उचित सुधार करें।

ह./–
(एम. वी. रमेशन)
उप सचिव (भर्ती एवं परीक्षा)

रिक्ति सूचना

अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन के अधीन कृषि विभाग द्वारा संयुक्त निदेशक (कृषि) के 01 (एक) पद को भरने का प्रस्ताव है। यह पद समूह 'क' (ग्रुप–।) राजपत्रित, गैर–मंत्रालयिक, स्तर–11 (रु. 67,700–2,08,700), सीसीएस (संशोधित वेतन) नियम, 2016 के अंतर्गत प्रतिनियुक्ति (अल्पकालिक अनुबंध सहित) के आधार पर भरा जाएगा।

इच्छुक एवं पात्र कर्मचारी/अधिकारी अपने आवेदन समाचार पत्र/अंडमान एवं निकोबार राज्य पोर्टल में विज्ञापन के प्रकाशन की तिथि से 45 दिनों के भीतर कृषि निदेशालय, श्री विजय पुरम – 744102 में प्रेषित कर सकते हैं/पहुँच जाने चाहिए। पात्र अभ्यर्थी आवेदन प्रपत्र वेबसाइट www.andamannicobar.gov.in से डाउनलोड कर सकते हैं।

सचिव (कृषि)
अण्डमान तथा निकोबार प्रशासन

सऊदी अरब में कुछ दवाइयाँ प्रतिबंधित, एनसीबी ने यात्रियों को किया सतर्क

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

सऊदी अरब की यात्रा करने वाले भारतीय नागरिकों के लिए एक अहम सूचना सामने आई है। नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) ने कहा है कि सऊदी अरब जाने या वहां से लौटने वाले यात्रियों को कुछ विशेष दवाएं साथ ले जाने से पहले अनुमति लेना अनिवार्य होगा। यह व्यवस्था सऊदी अरब द्वारा लागू किए गए नए ऑनलाइन क्लीयरेंस सिस्टम के तहत की गई है।

नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के अनुसार, सऊदी अरब के जनरल डायरेक्टरेट ऑफ नारकोटिक्स कंट्रोल ने भारत को सूचित किया है कि कुछ दवाएं, जो भारत या अन्य देशों में कानूनी रूप से उपलब्ध हैं। वो सऊदी में प्रतिबंधित या सीमित श्रेणी में आती हैं। इसके अलावा तय सीमा से अधिक मात्रा में दवाएं ले जाने पर कार्रवाई भी हो सकती है।

सऊदी अरब ने दवाओं के लिए एक इलेक्ट्रॉनिक सेवा प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पोर्टल के जरिए यात्री व्यक्तिगत उपयोग के लिए ले जाई जाने वाली दवाओं की अनुमति ऑनलाइन ले सकते हैं। एनसीबी ने कहा है कि आवेदन यात्री स्वयं या उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा किया जा सकता है।

एनसीबी ने यात्रियों को सलाह दी है कि वे यात्रा से पहले सऊदी अधिकारियों द्वारा जारी प्रतिबंधित और निषिद्ध दवाओं की आधिकारिक सूची जरूर देख लें। जिन दवाओं को ले जाने की योजना है, उनकी अनुमति है या नहीं, इसकी जांच करना जरूरी है। एजेंसी ने साफ किया है कि बिना अनुमति या तय सीमा से ज्यादा दवाएं ले जाने पर सऊदी अरब में कानूनी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में नियामक कार्रवाई

नए लेबर कोड से गिग वर्कर्स को बड़ी राहत, न्यूनतम वेतन और सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

नए लेबर कोड के लागू होने से गिग और प्लेटफॉर्म वर्कर्स को बड़ा लाभ मिलने वाला है। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने चारों लेबर कोड से जुड़े ड्राफ्ट नियम जारी कर दिए हैं, जिनके तहत गिग वर्कर्स को न्यूनतम वेतन, स्वास्थ्य, व्यावसायिक सुरक्षा और सामाजिक सुरक्षा जैसे अधिकार मिलेंगे।

सरकार ने इन ड्राफ्ट नियमों पर सभी हितधारकों से फीडबैक मांगा है। उद्देश्य है कि चारों लेबर कोड को एक अप्रैल से पूरे देश में लागू किया जाए। यह जानकारी 30 दिसंबर, 2025 को जारी नोटिफिकेशन में दी गई।

ड्राफ्ट नियमों के अनुसार, सामाजिक सुरक्षा का लाभ पाने के लिए किसी गिग कर्मचारी का किसी एक प्लेटफॉर्म से कम से कम 90 दिनों तक जुड़ा होना जरूरी होगा। यदि कोई गिग कर्मचारी एक साथ दो प्लेटफॉर्म पर काम करता है, तो यह अवधि 120 दिन निर्धारित की गई है।

नियमों में यह भी स्पष्ट किया गया है कि किसी भी कैलेंडर दिन में यदि कर्मचारी किसी एग्रीगेटर के लिए किए गए कार्य से आय अर्जित करता है, तो उसे उस दिन "कार्यरत" माना जाएगा, भले ही आय की राशि कितनी भी हो। यदि कोई कर्मचारी एक से अधिक एग्रीगेटरों से जुड़ा है, तो सभी प्लेटफॉर्म पर किए गए कार्य दिवसों को जोड़कर गणना की जाएगी। ड्राफ्ट में यह भी प्रावधान किया गया है कि यदि कोई कर्मचारी एक ही कैलेंडर दिन में तीन एग्रीगेटरों के लिए काम करता है, तो उसे तीन अलग–अलग कार्य दिवसों के रूप में गिना जाएगा।

न्यूनतम मजदूरी को लेकर ड्राफ्ट में कहा गया है कि जब एक दिन की मजदूरी तय की जाएगी, तो उसे आठ से विभाजित कर प्रति घंटे की मजदूरी और 26 से गुणा कर मासिक मजदूरी तय की जाएगी। न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करते समय केंद्र सरकार भौगोलिक क्षेत्र, अनुभव और कौशल स्तर– अकुशल, अर्धकुशल, कुशल और उच्च कुशल– जैसे कारकों को ध्यान में रखेगी।

वेतन संहिता, 2019; औद्योगिक संबंध संहिता, 2020; सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020; और व्यावसायिक सुरक्षा, स्वास्थ्य एवं कार्य परिस्थितियां संहिता, 2020 को एक साथ अधिसूचित किया गया है। श्रम संहिताओं के तहत नियोक्ताओं के लिए सभी श्रमिकों को नियुक्ति पत्र जारी करना अनिवार्य किया गया है, जिससे पारदर्शिता, नौकरी की सुरक्षा और रोजगार में स्थिरता सुनिश्चित होगी। इससे पहले नियुक्ति पत्र देना अनिवार्य नहीं था।

सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 के तहत गिग और प्लेटफॉर्म श्रमिकों सहित सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा कवरेज मिलेगा। इसके अंतर्गत पीएफ, ईएसआईसी, बीमा और अन्य सामाजिक सुरक्षा लाभ शामिल होंगे, जबकि पहले यह कवरेज सीमित था।

इसी तरह, मजदूरी संहिता, 2019 के तहत सभी श्रमिकों को वैधानिक न्यूनतम मजदूरी और समय पर भुगतान का अधिकार मिलेगा। पहले न्यूनतम मजदूरी केवल अनुसूचित उद्योगों और रोजगारों तक सीमित थी, जिससे श्रमिकों का बड़ा वर्ग इससे वंचित रह जाता था।

इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट पीएलआई में 22 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी, 41,863 करोड़ रुपए के निवेश की उम्मीद

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

सरकार ने इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (ईसीएमएस) के तहत 22 नए प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं से करीब 41,863 करोड़ रुपए के निवेश और 37,000 से अधिक प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की उम्मीद है।

इन प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति मजबूत होगी और आयात पर निर्भरता में कमी आएगी। मंजूरी प्राप्त 22 परियोजनाओं से लगभग 2.58 लाख करोड़ रुपए के उत्पादन का अनुमान है। स्वीकृत परियोजनाओं में डिक्सन टेक्नोलॉजीज, सैमसंग डिस्प्ले नोएडा प्राइवेट लिमिटेड, फॉक्सकॉन की युझान टेक्नोलॉजी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड और हिंडाल्को इंडस्ट्रीज जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं। यह मंजूरी पहले स्वी.त 24 आवेदनों के अतिरिक्त है, जिनमें 12,704 करोड़ रुपए का निवेश किया गया था।

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अनुसार, इस चरण की स्वीकृतियों में मोबाइल फोन, दूरसंचार, उपभोक्ता इलेक्ट्रॉनिक्स, रणनीतिक इलेक्ट्रॉनिक्स, ऑटोमोटिव और आईटी हार्डवेयर सहित कुल 11 क्षेत्रों में विनिर्माण गतिविधियां शामिल हैं। ये परियोजनाएं आठ राज्यों– आंध्र प्रदेश, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश और राजस्थान में स्थापित की जाएंगी। इंडस्ट्री लीडर्स ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण में भारत के इरादों से क्रियान्वयन की ओर निर्णायक कदम बताया। आईईएसए और एसईएमआई इंडिया के अध्यक्ष अशोक चंदक ने कहा, "2025 के अंत तक भारत ने एक विश्वसनीय और निवेश योग्य ईएसडीएम गंतव्य के रूप में वैश्विक विश्वास अर्जित कर लिया है।

ईसीएमएस एक क्रांतिकारी बदलाव है, क्योंकि मजबूत पारिस्थितिकी तंत्र के लिए केवल सेमीकंडक्टर ही नहीं, बल्कि कंपोनेंट्स, मैटेरियल्स और इलेक्ट्रॉनिक्स वैल्यू एडिशन भी आवश्यक हैं।" उन्होंने कहा कि अगले चरण में उत्पादन बढ़ाने, मजबूत डिजाइन टीमों के निर्माण, स्थानीय स्तर पर सोर्सिंग और निर्मित उत्पादों में विश्व स्तरीय गुणवत्ता सुनिश्चित करने पर ध्यान केंद्रित करना होगा। ओईएम और सिस्टम कंपनियों को मेड–इन–इंडिया कंपोनेंट्स को सक्रिय रूप से अपनाना चाहिए, क्योंकि मांग सृजन आपूर्ति सृजन जितना ही महत्वपूर्ण है।

तंबाकू उत्पादों पर सरकार का बड़ा फैसला! सिगरेट–गुटखा होंगे महंगे, 1 फरवरी से लागू होंगी नई दरें

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

सरकार ने तंबाकू और उससे जुड़े उत्पादों पर सख्ती बढ़ाते हुए एक अहम कदम उठाया है। केंद्र सरकार ने स्वास्थ्य सुरक्षा से जुड़ा नया उपकर लागू करने की घोषणा की है, जो 1 फरवरी से प्रभावी होगा। इसके साथ ही कई तंबाकू उत्पादों पर जीएसटी की नई दरें भी तय कर दी गई हैं। बुधवार देर रात वित्त मंत्रालय ने इससे जुड़ी अधिसूचनाएं जारी कीं।

शीतकालीन सत्र में संसद ने उपकर से जुड़ा विधेयक पास किया था। इसमें सामान बनाने, मशीनरी लगाने या प्रक्रिया करने पर उपकर लगाने का प्रावधान है। इस उपकर से होने वाली कमाई केंद्र के समेकित कोष में जाएगी और इसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य से जुड़े खर्चों में होगा। शुरुआत में इसे पान मसाले पर लागू किया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पर दूसरे सामानों पर भी लगाया जा सकता है।

नई अधिसूचना के मुताबिक, बीड़ी पर 18 प्रतिशत जीएसटी लगाया गया है।

पान मसाला, तंबाकू, सिगरेट, सिगार, चेरूट, गुटखा और अन्य तंबाकू उत्पादों पर 40 प्रतिशत जीएसटी लागू होगा। बिना धुएं वाले तंबाकू उत्पाद और निकोटीन आधारित चीजें भी इसी दायरे में आएंगी।

इसका सीधा असर इन उत्पादों की कीमतों पर पड़ेगा, जिससे आम उपभोक्ताओं को ज्यादा कीमत चुकानी पड़ सकती है।

यह फैसला संसद के शीतकालीन सत्र में पारित विधेयक के आधार पर लिया गया है। सरकार का मानना है कि इससे न सिर्फ तंबाकू सेवन पर लगाम लगेगी, बल्कि इससे मिलने वाली राशि से स्वास्थ्य से जुड़ी योजनाओं को भी मजबूती मिलेगी।

सरकार का यह कदम स्वास्थ्य और सुरक्षा दोनों को ध्यान में रखकर उठाया गया है। नई दरें लागू होने से तंबाकू उत्पादों पर टैक्स का बोझ बढ़ेगा और इससे सरकार को अतिरिक्त राजस्व मिलेगा, जिसका इस्तेमाल राष्ट्रीय सुरक्षा और सार्वजनिक स्वास्थ्य पर किया जाएगा।

आईआईएमसी की 60 साल की शैक्षणिक विरासत में नया अध्याय, पहली बार पीएच.डी. पाठ्यक्रम की शुरुआत

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

भारतीय जनसंचार संस्थान (डीम्ड विश्वविद्यालय) ने 1 जनवरी 2026 को औपचारिक रूप से अपने पीएच.डी. पाठ्यक्रम का शुभारंभ किया, जो संस्थान की 60 वर्षों की शैक्षणिक यात्रा में एक ऐतिहासिक पड़ाव है। शैक्षणिक वर्ष 2025–26 के लिए पीएच.डी. पाठ्यक्रम में प्रवेश हेतु शोधार्थियों का चयन किया जाएगा।

पूर्णकालिक और अंशकालिक दोनों श्रेणियों के उम्मीदवारों के लिए ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया 1 जनवरी 2026 से शुरू हो गई है और यह 30 जनवरी 2026 तक जारी रहेगी। यूजीसी–नेट योग्यता वाले उम्मीदवारों को सीधे साक्षात्कार के लिए बुलाया जाएगा। वहीं, यूजीसी–नेट के बिना आवेदन करने वाले अंशकालिक उम्मीदवारों को 15 फरवरी 2026 को आयोजित होने वाली प्रवेश परीक्षा देनी होगी। चयनित उम्मीदवारों की सूची 23 फरवरी 2026 को जारी की जाएगी और साक्षात्कार 9 मार्च 2026 से शुरू होंगे। प्रवेश की पूरी प्रक्रिया 27 मार्च 2026 तक पूरी कर ली जाएगी और कोर्सवर्क की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 से होगी।

आईआईएमसी के पीएच.डी. पाठ्यक्रम की परिकल्पना एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण प्रदान करने, इंटरडिसिप्लिनरी स्कॉलरशिप को प्रोत्साहित करने और पत्रकारिता, संचार एवं संबद्ध क्षेत्रों में विकसित हो रहे ज्ञान के भंडार में योगदान देने के लिए की गई है।

केन्द्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने भारतीय फार्माकोपिया का 10वां संस्करण जारी किया

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने आज राजस्थान और महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्रियों और वरिष्ठ अधिकारियों के साथ स्वास्थ्य सेवा वितरण तंत्र का मूल्यांकन करने के लिए एक समीक्षा बैठक की। चर्चा का केंद्र बिंदु सार्वजनिक स्वास्थ्य अवसंरचना को सुदृढ़ करना, रोगी–केंद्रित सेवाओं में सुधार करना, नियामक ढाँचों को मजबूत करना और सार्वजनिक स्वास्थ्य चुनौती के रूप में तपेदिक को समाप्त करने की देश की प्रतिबद्धता को आगे बढ़ाना था।

स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने एक सशक्त और सतर्क औषधि नियामक प्रणाली की भूमिका पर बल दिया। उन्होंने कहा कि गुणवत्ता, सुरक्षा और जन विश्वास सुनिश्चित करने के लिए उत्पादन से लेकर अंतिम व्यक्ति तक वितरण की संपूर्ण निगरानी अनिवार्य है। उन्होंने सर्वोत्तम नियामक प्रथाओं को अपनाने का आह्वान किया और कहा कि रोगी संतुष्टि, अनुपालन और नियामक पर्यवेक्षण को निरंतर और सतत प्रयास के रूप में जारी रखा जाना चाहिए।

भारत में सक्रिय हुई गूगल की Android इमरजेंसी लोकेशन सेवा

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

Android स्मार्टफोन यूजर्स के लिए गूगल ने एक बेहद महत्वपूर्ण सुरक्षा फीचर 'इमरजेंसी लाइव वीडियो' की घोषणा की है। यह फीचर आपातकालीन स्थितियों में यूजर्स के लिए अत्यंत उपयोगी होगा, जहां वे लाइव वीडियो स्ट्रीमिंग के जरिए तुरंत मदद बुला पाएंगे।

यह नया फीचर Android की मौजूदा इमरजेंसी लोकेशन सर्विस पर आधारित है, जो संकट की स्थिति में न केवल सटीक लोकेशन, बल्कि घटनास्थल का रियल–टाइम दृश्य भी प्रदान करेगा। गूगल के ब्लॉग पोस्ट के अनुसार, जब आप इमरजेंसी कॉल या टेक्स्ट करते हैं, तो एक डिस्पैचर (आपातकालीन सेवाओं का कर्मचारी) आपके फोन पर लाइव वीडियो शेयर करने के लिए रिक्वेस्ट भेज सकता है। यूजर्स सिर्फ एक टैप करके अपने कैमरे से सुरक्षित रूप से स्ट्रीमिंग शुरू कर सकते हैं।

यह रियल–टाइम व्यू रेस्पॉन्डर को घटनास्थल की स्थिति का जल्दी से आकलन करने में मदद करेगा, जिससे डिस्पैचर को उसी समय सही मदद मिल पाएगी। यह मदद आने तक CPR जैसे जान बचाने वाले कदम उठाने में भी सहायक हो सकता है।

गूगल ने दावा किया है कि इस फीचर को पूरी तरह से सुरक्षित बनाया गया है। यह फीचर एन्क्रिप्टेड है। Android यूजर्स हमेशा यह कंट्रोल कर सकते हैं कि उनका वीडियो शेयर किया जाए या नहीं, और वे किसी भी समय तुरंत शेयरिंग को बंद कर सकते हैं। यह फीचर इस्तेमाल करने के लिए किसी सेटअप की जरूरत नहीं है।

इमरजेंसी लाइव वीडियो फीचर वर्तमान में अमेरिका के साथ–साथ जर्मनी और मेक्सिको के कुछ खास इलाकों में रोल आउट हो रहा है। यह Google Play सर्विसेज वाले Android 8+ पर चलने वाले सभी Android फोन पर सपोर्ट करता है। उम्मीद है कि इसे भारत के साथ–साथ अन्य देशों में भी आगे आने वाले समय में रोल आउट किया जा सकता है।

गूगल का कहना है कि उसने इस फ़ीचर को आसान और सुरक्षित बनाया है। इसे इस्तेमाल करने के लिए यूज़र्स को किसी सेटअप की ज़रूरत नहीं है। इमरजेंसी कॉल या टेक्स्ट के दौरान, अगर जवाब देने वाले को लगता है कि घटनास्थल देखना मददगार और सुरक्षित होगा, तो वे आपके डिवाइस पर एक रिक्वेस्ट भेज सकते हैं। इसके बाद स्क्रीन पर एक प्रॉम्प्ट दिखाई देगा। यूज़र्स फिर "शेयर" पर टैप करके अपने कैमरे से लाइव वीडियो सुरक्षित रूप से शेयर कर सकते हैं।

इतिहास के पन्नों में 03 जनवरी: सावित्रीबाई फुले–भारत की पहली महिला शिक्षिका और सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

वर्ष 1831 में जन्मी सावित्रीबाई फुले भारतीय समाज में सामाजिक परिवर्तन की अग्रदूत थीं। वे न केवल भारत की पहली महिला शिक्षिका थीं, बल्कि मराठी भाषा की पहली महिला कवयित्री और एक साहसी समाज सुधारक भी थीं। उनका जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उस समय समाज में महिलाओं और दलितों की शिक्षा का विरोध किया जाता था, लेकिन सावित्रीबाई फुले ने इन रूढ़ियों को चुनौती दी।

अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले के सहयोग से उन्होंने 1848 में पुणे में देश का पहला बालिका विद्यालय शुरू किया। यह कदम उस दौर में क्रांतिकारी माना जाता था। पढ़ाने जाते समय उन्हें सामाजिक विरोध, अपमान और हिंसा तक का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। सावित्रीबाई ने विधवा पुनर्विवाह, महिला शिक्षा और दलित उत्थान के लिए भी सक्रिय रूप से काम किया।

वे एक संवेदनशील कवयित्री भी थीं, जिनकी कविताओं में सामाजिक समानता, शिक्षा और मानवता का संदेश झलकता है। 1897 में प्लेग महामारी के दौरान रोगियों की सेवा करते हुए वे स्वयं इस बीमारी की चपेट में आ गईं और उनका निधन हो गया। सावित्रीबाई फुले का जीवन साहस, करुणा और समानता के संघर्ष की प्रेरणादायक मिसाल है, जो आज भी समाज को दिशा देता है।

महत्वपूर्ण घटनाचक्र–1833 – ब्रिटेन ने दक्षिण अटलांटिक के फॉकलैंड द्वीप पर कब्जा जमाया।

1880 – 'इलस्ट्रेटिड वीकली ऑफ इंडिया' का पहला अंक बम्बई में प्रकाशित।

1894 – रवीन्द्र नाथ टैगोर ने 'शांति निकेतन' में 'पौष मेला' का उद्घाटन किया।

1901 – 'शांति निकेतन' में ब्रह्मचर्य आश्रम खुला।

1911 – अमेरिका में डाक बचत बैंक का उद्घाटन हुआ।

1929 – महात्मा गांधी लॉर्ड इरविन से मिले।

1938 – अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति डी रूजवेल्ट ने पोलियो की बीमारी का इलाज ढूंढने के लिए एक फाउंडेशन की स्थापना की। रूजवेल्ड 1921 में इस बीमारी की चपेट में आए थे।

1943 – टेलीविजन पर पहली बार गुमशुदा लोगों के बारे में सूचना का प्रसारण किया गया।

1956 – फ्रांस में 'एफिल टॉवर' के ऊपरी हिस्से में आग लगने से नुकसान।

1957 – अमेरिका के पेनसिल्वेनिया में पहली बार बिजली घड़ी प्रदर्शित की गयी।

1959 – अलास्का को अमेरिका का 49वां राज्य घोषित किया गया।

1968 – देश के पहले मौसम विज्ञान रॉकेट 'मेनका' का प्रक्षेपण।

1991 – इजरायल ने 23 साल बाद सोवियत संघ में वाणिज्य दूतावास को दोबारा खोला।

1993 – अमरीका और रूस ने अपने परमाणु हथियारों की संख्या को आधा करने पर सहमति जतायी।

1995 – हरियाणा के डबवाली में एक स्कूल में लगी भीषण आग में 360 लोगों की मौत।

1998 – अल्जीरियाई इस्लामी विद्रोह में 412 लोगों की हत्या।

2000 – कलकत्ता का नाम आधिकारिक रूप से कोलकाता रखा गया।

शिक्षा मंत्रालय की पहल, हर उम्र के छात्रों के लिए उनकी ही भाषा में निशुल्क ई–बुक्स

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय, डिजिटल पहल के तहत राष्ट्रीय ई–पुस्तकालय कार्यक्रम चला रहा है। शिक्षा मंत्रालय के मुताबिक केंद्र सरकार की इस योजना में अब 6000 से अधिक निशुल्क ई–बुक्स देश भर के पाठकों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं।

यही नहीं, इस उपलब्धि के साथ साथ साल 2026 को पठन वर्ष के रूप में चिह्नित करने का आह्वान किया जा रहा है। यह कदम इसलिए उठाया जा रहा है ताकि देश में पढ़ने की संस्कृति और आदत को और अधिक प्रोत्साहन मिले। शिक्षा मंत्रालय ने राष्ट्रीय ई–पुस्तकालय नामक इस महत्वपूर्ण डिजिटल लाइब्रेरी प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया था। अब इसमें जो 6000 से अधिक निशुल्क ई– पुस्तकें पाठकों के लिए उपलब्ध कराई गई हैं, उनमें लगभग सभी आयु वर्ग के छात्रों का ध्यान रखा गया है।

शिक्षा मंत्रालय के अनुसार यूं तो यह पहल सभी उम्र के पाठकों के लिए है, लेकिन फिर भी विशेषकर बच्चों और किशोरों के लिए ज्ञान, मनोरंजन और सीखने के अवसरों को बढ़ावा दिया जा रहा है। बच्चों और किशोरों के ज्ञान में वृद्धि के उद्देश्य से यह शुरुआत की गई है।

दरअसल राष्ट्रीय ई–पुस्तकालय एक राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी है जिसे शिक्षा मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया है। इस लाइब्रेरी में हास्य, साहित्य, इतिहास, विज्ञान, जीवनी, कविता, कॉमिक्स, और अन्य कई विषयों की निशुल्क ई–बुक्स शामिल की गई हैं, जो विभिन्न उम्र के पाठकों के लिए उपयुक्त हैं।

इस लाइब्रेरी की एक बड़ी खासियत यह भी है कि इसे देश के हर राज्य व प्रत्येक हिस्से को ध्यान में रखकर तैयार किया गया है। यही कारण है कि यहां 23 अलग–अलग भारतीय भाषाओं में किताबें उपलब्ध कराई गई हैं। ऐसा करते समय भारत की भाषाई विविधता को ध्यान में रखा गया। इसका एक बड़ा लाभ यह है कि इस ई–पुस्तकालय की पहुंच अधिक से अधिक लोगों तक सुनिश्चित होती है। ये ई–बुक्स वेब, एंड्रॉइड और आइओएस ऐप सभी प्लेटफॉर्म पर पढ़ी जा सकती हैं।

इस पहल के तहत एक खास मोबाइल एप्लिकेशन भी विकसित की गई है। इस मोबाइल एप्लिकेशन के पाठक कहीं भी, कभी भी ई–बुक्स को पढ़ सकते हैं। शिक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों का कहना है कि इस ऐप में उम्र के अनुसार विभिन्न श्रेणियों में पुस्तकें प्राप्त करने व पढ़ाने की सुविधा है। आयु को आधार बनाकर 3 से 8 वर्ष, 8 से 11 वर्ष, 11 से 14 वर्ष व 14 से 18 वर्ष के बच्चों के लिए किताबें ढूंढने की सुविधा है।

आयुष मंत्रालय आज से चेन्नई में 9वें सिद्ध दिवस समारोह का आयोजित करेगा

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

आयुष मंत्रालय शनिवार को चेन्नई के कलाइवनार अरंगम में 9वें सिद्ध दिवस का आयोजन करेगा। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय सिद्ध संस्थान (एनआईएस), केंद्रीय सिद्ध अनुसंधान परिषद (सीसीआरएस) और तमिलनाडु सरकार के भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी निदेशालय के सहयोग से आयोजित किया जाएगा।

"वैश्विक स्वास्थ्य के लिए सिद्ध" विषय पर आधारित यह समारोह, सिद्ध चिकित्सा के जनक माने जाने वाले ऋषि अगस्त्य की जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया जा रहा है। सिद्ध दिवस प्रतिवर्ष 6 जनवरी को मनाया जाता है।

आयुष के अनुसार, उपराष्ट्रपति सी.पी. राधाकृष्णन नौवें सिद्ध दिवस समारोह का उद्घाटन करेंगे और उसकी अध्यक्षता भी करेंगे। इस समारोह में तमिलनाडु और अन्य राज्यों के सिद्ध चिकित्सक, वैज्ञानिक, शिक्षाविद, विद्वान और छात्र एक मंच पर जुटेंगे। सिद्ध वैधानिक निकायों के वरिष्ठ सदस्य, एनआईएस और सीसीआरएस के शोधकर्ता, साथ ही आयुष मंत्रालय और तमिलनाडु सरकार के अधिकारी भी इसमें भाग लेंगे।

कार्यक्रम में चेन्नई और पलायमकोट्टई के सरकारी सिद्ध मेडिकल कॉलेजों और तमिलनाडु और केरल के स्व–वित्तपोषित सिद्ध कॉलेजों के स्नातक, स्नातकोत्तर और

डॉक्टरेट छात्रों की भी बड़ी संख्या में उपस्थित रहने की उम्मीद है।

इस अवसर पर आयुष मंत्रालय सिद्ध चिकित्सा पद्धति में असाधारण योगदान देने वाले पांच प्रतिष्ठित व्यक्तियों को सम्मानित करेगा। नौवें सिद्ध दिवस के अवसर पर निवारक स्वास्थ्य, अनुसंधान और वैश्विक कल्याण में सिद्ध चिकित्सा के योगदान को दर्शाया जाएगा। इसका उद्देश्य जागरूकता बढ़ाना और स्वास्थ्य सेवा वितरण, अनुसंधान सहयोग और शैक्षणिक प्रगति में सिद्ध चिकित्सा की भूमिका को मजबूत करने की दिशा में सरकार के निरंतर प्रयासों को सामने लाना है।

आज सूरज के सबसे पास पहुंच रही पृथ्वी, सुपरमून जैसा दिखेगा पूर्णिमा का चांद

भोपाल, 02 जनवरी।

खगोल विज्ञान में रुचि रखने वाले लोगों के लिए शनिवार, 03 जनवरी का दिन बेहद खास होने जा रहा है। इस दिन पृथ्वी पर नए साल का जश्न मनाने के लिए चंद्रमा और सूर्य दोनों हमारे सबसे पास आ रहे हैं, जहां चंद्रमा पृथ्वी के पास आकर लगभग सुपरमून जैसा होगा तो पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करते हुए उस बिंदु पर पहुंच रही है, जो सूर्य के सबसे नजदीक है।

मध्य प्रदेश की नेशनल अवार्ड प्राप्त विज्ञान प्रसारक सारिका घारू ने इस खगोलीय घटना की जानकारी देते हुए बताया कि आकाशमंडल के सभी पिंड अपनी परिक्रमा अंडाकार पथ में करते हैं, जिससे पूरी परिक्रमा के दौरान ये एक बार सबसे पास के बिंदु पर आते हैं तो एक बार सबसे दूर पहुंच जाते हैं और नये साल की शुरुआत में इनके पास आने की स्थिति आ रही है। उन्होंने बताया कि पास आने की यह स्थिति पेरिहेलियन कहलाती है।

सारिका ने बताया कि शनिवार रात्रि 10 बजकर 45 मिनट पर पृथ्वी इस साल सूर्य के सबसे निकट पहुंच जाएगी और इसकी दूरी घटकर 14 करोड़ 70 लाख 99 हजार 894 किलोमीटर रह जायेगी जबकि जुलाई में यह दूरी बढ़कर 15 करोड़ 20 लाख 87 हजार 774 किलोमीटर हो जाएगी।

उन्होंने बताया कि अनेक सोशल मीडिया पर शनिवार के चंद्रमा को वुल्फ सुपरमून के रूप मे बताया गया है। खगोल विज्ञान की दृष्टि से चंद्रमा एक जनवरी को पृथ्वी के सबसे नजदीक बिंदु पर पहुंचा था। अब यह दूर होना शुरू हो चुका है, इसलिये यह सुपरमून जैसा है, पूरी तरह सुपरमून नहीं है। शनिवार को पूर्णिमा की अवस्था में पहुंचने पर चंद्रमा मिथुन राशि में स्थित रहते हुये पृथ्वी से लगभग तीन लाख 62 हजार किलोमीटर की दूरी पर होगा और यह शाम उदित होकर रात भर आकाश में रहेगा। अगर आप वास्तविक सबसे बड़े और चमकदार सुपरमून को देखना चाहते हैं तो इसके लिए 24 दिसम्बर का इंतजार करना होगा।

सर्फिंगः एक रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स, जिसने ओलंपिक में भी बना ली जगह

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

सर्फिंग एक रोमांचक वाटर स्पोर्ट्स है, जिसमें खिलाड़ी समुद्र की लहरों पर एक विशेष बोर्ड के सहारे संतुलन बनाते हुए करतब दिखाते हैं। ताकत, संतुलन, धैर्य और समय की समझ का यह खेल तटीय क्षेत्रों में बेहद लोकप्रिय है। 400 ईस्वी में पोलिनेशियन मछुआरे मछली पकड़ने के लिए सरकंडे की नावों का इस्तेमाल करते थे, जिसे सर्फिंग का शुरुआती रूप माना गया।

खगोलीय माप लेने में माहिर रॉयल नेवी के अधिकारी जेम्स किंग मशहूर खोजकर्ता कैप्टन कुक की तीसरी और अंतिम विश्व यात्रा (1776–1780) के दौरान उनके साथ थे। कुक की मृत्यु के बाद, जेम्स किंग ने जहाजों को घर ले जाने और कुक के यात्रा विवरण को पूरा करने का जिम्मा संभाला। उन्होंने कुक की मृत्यु के बाद सर्फिंग के बारे में लिखा, जिसने इस खेल के प्रति लोगों की रुचि को बढ़ाने का काम किया।

हवाई में जन्मे लाइफगार्ड जॉर्ज फ्रीथ को 'फादर ऑफ मॉडर्न सर्फिंग' कहा जाता है, जिन्होंने 20वीं सदी की शुरुआत में एक पोत बनाने के लिए 5 मीटर हार्डवुड के बोर्ड को काटकर मॉर्डन सर्फिंग का रूप दिया। दूसरी ओर, तीन बार के ओलंपिक स्विमिंग चैंपियन ड्यूक काहनमोकू ने संयुक्त राज्य अमेरिका में इस खेल को लोकप्रिय बनाने में योगदान दिया।

इसके बाद काहनमोकू इस खेल को ऑस्ट्रेलिया लेकर गए, जहां इसे ओलंपिक गेम्स में शामिल करने की पेशकश की। 2020 टोक्यो ओलंपिक में सर्फिंग ने ओलंपिक डेब्यू किया, जिसमें 20 पुरुष और 20 महिला एथलीट्स शामिल थे, जिसमें शॉर्टबोर्ड का इस्तेमाल किया गया। ब्राजील

पुरुषों की कैटेगरी में इस खेल का पहला ओलंपिक चैंपियन बना। वहीं, संयुक्त राज्य अमेरिका ने महिलाओं की कैटेगरी में गोल्ड जीता।

सर्फिंग में दो और चार एथलीट्स के बीच एक हीट प्रतियोगिता होती है, जिसमें शानदार वेव को पकड़ने के लिए 20–30 मिनट का समय दिया जाता है। एक बार में सिर्फ एक ही सर्फर वेव की सवारी कर सकता है। जजों का पैनल दो बेस्ट राइडर का चयन करता है, जिन्हें प्रत्येक वेव में प्रदर्शन के आधार पर 10 में से अंक दिए जाते हैं। इस दौरान वेव के साथ तालमेल, मुश्किल हालात और वेव के अलग–अलग प्रकार के आधार पर अंक तय किए जाते हैं।

भारत को इस खेल में ओलंपिक पदक जीतने के लिए बेहतर बुनियादी ढांचे, निरंतर प्रशिक्षण, अंतरराष्ट्रीय अनुभव और युवा प्रतिभाओं को बढ़ावा देने की जरूरत है। विशेषज्ञ कोच इस खेल में भारत के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को तैयार कर सकते हैं।

19 राज्यों में घर बैठे डाउनलोड कर सकेंगे ज़मीन के कागजात, खरीद–बिक्री और लोन मिलने में होगी आसानी

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

अब देश के 19 राज्यों के नागरिक अपने जमीन के कागजात (लैंड रिकॉर्ड) घर बैठे डिजिटल रूप में डाउनलोड कर सकेंगे। ये कागज कानूनी रूप से मान्य होंगे। इसके अलावा, 406 जिलों में बैंक अब ऑनलाइन ही जमीन गिरवी रखने (मॉर्गेज) की जानकारी जांच सकते हैं, जिससे लोगों को लोन जल्दी मिलने में मदद मिलेगी।

सरकार के मुताबिक, भूमि संसाधन विभाग ने जमीन के रिकॉर्ड को डिजिटल बनाने का काम लगभग पूरा कर लिया है। इससे जमीन से जुड़े काम अब लाइन में लगकर नहीं, बल्कि ऑनलाइन होने लगे हैं।

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, देश के 97 प्रतिशत से ज्यादा गांवों में जमीन के अधिकार से जुड़े रिकॉर्ड कंप्यूटर पर दर्ज किए जा चुके हैं। लगभग 97 प्रतिशत जमीन के नक्शे भी डिजिटल बना दिए गए हैं। करीब 85 प्रतिशत गांवों में जमीन के लिखित रिकॉर्ड को नक्शों से जोड़ दिया गया है।

(एनएकेएसएचए) यानी 'राष्ट्रीय भू–स्थानिक ज्ञान–आधारित शहरी आवास भूमि सर्वेक्षण' योजना शुरू की गई है। इस योजना के तहत देश के 157 शहरी स्थानीय निकायों (यूएलबी) में काम किया जा रहा है। इनमें से 116 यूएलबी में हवाई सर्वे पूरा हो चुका है, जिसमें हाई–रिजॉल्यूशन इमेज के साथ 5,915 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र को कवर किया गया।

सरकार ने बताया कि 72 शहरों में जमीनी स्तर पर जांच शुरू हो चुकी है और 21 शहरों में यह काम पूरी तरह खत्म हो गया है। केंद्र सरकार ने 2025–26 की योजना के तहत 24 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 1,050 करोड़ रुपए

की सहायता मंजूर की है, ताकि वे जमीन के डिजिटल रिकॉर्ड का काम पूरा कर सकें।

सरकार ने जमीन के लिए एक खास पहचान संख्या भी शुरू की है, जिसे यूएलपीआईएन कहा जाता है। यह 14 अंकों का नंबर होता है और इसे जमीन का आधार कार्ड कहा जा रहा है। नवंबर 2025 तक देश के 29 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 36 करोड़ से ज्यादा लैंड पार्सल को यह नंबर दिया जा चुका है।

मंत्रालय के अनुसार, सरकार ने राष्ट्रीय दस्तावेज पंजीकरण प्रणाली (एनजीडीआरएस) शुरू की है, जिससे जमीन की खरीद–बिक्री आसान हो गई है। यह सिस्टम पंजाब, महाराष्ट्र और हिमाचल प्रदेश सहित 17 राज्यों में लागू हो चुका है।

करीब 88 प्रतिशत सब रजिस्ट्रार ऑफिस (एसआरओ) अब राजस्व कार्यालयों के साथ जुड़ चुके हैं, जिससे रजिस्ट्रेशन के तुरंत बाद जमीन का रिकॉर्ड अपने आप अपडेट हो जाता है। सरकार का कहना है कि इन सभी कदमों से जमीन से जुड़े काम आसान, तेज और पारदर्शी हो गए हैं।

अब लद्दाख के उप राज्यपाल 100 करोड़ रुपये तक की परियोजना को मंजूरी दे सकेंगे

जम्मू, 02 जनवरी।

केंद्र सरकार ने लद्दाख के उप राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां बहाल कर दी हैं। इसके बाद अब उपराज्यपाल 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अपने अधिकारों का इस्तेमाल कर सकेंगे।

वित्त मंत्रालय ने लद्दाख, अंडमान तथा निकोबार द्वीप समूह, चंडीगढ़, दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव और लक्षद्वीप के प्रशासकों और उप राज्यपालों को 100 करोड़ रुपये तक की परियोजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के लिए अधिकार सौंप दिया है। मंत्रालय के अनुसार वित्तीय शक्तियों के प्रत्यायोजन नियम (डीएफपीआर), 2024 के तहत एलजी और प्रशासकों को शक्तियां प्रदान की गई हैं। मंत्रालय के अनुसार इन शक्तियों का प्रयोग एलजी/प्रशासक संबंधित यूटी के सचिव (वित्त) या वित्तीय सलाहकार के परामर्श से, साथ ही पर्याप्त बजटीय प्रावधान उपलब्ध होने के बाद करेंगे। वित्त मंत्रालय के निर्देश में कहा गया है कि प्रत्यायोजित शक्तियों को फिर से प्रत्यायोजित नहीं किया जा सकता है।

यह भी निर्देश दिये गए हैं कि इन शक्तियों के तहत स्वीकृत सभी प्रस्तावों का विवरण जुलाई, अक्टूबर, जनवरी और अप्रैल के अंत तक गृह मंत्रालय के माध्यम से व्यय विभाग को त्रैमासिक प्रस्तुत किया जाना चाहिए। पत्र के अनुसार डीएफपीआर, 2024 के नियम 16 के तहत प्रशासकों और एलजी की सैद्धांतिक मंजूरी से अंतिम मंजूरी तक व्यय को मंजूरी देने की शक्तियां जारी रहेंगी, लेकिन सक्षम अधिकारी योजनाओं के मूल्यांकन और अनुमोदन के बाद ही।

सांख्यिकी मंत्रालय ने पहली बार 'अपने सर्वेक्षण को जानें' सुगम मार्गदर्शिका जारी की

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने उपयोगकर्ताओं के साथ सक्रिय रूप से जुड़ने और सर्वेक्षण प्रक्रियाओं को अधिक पारदर्शी और उपयोगकर्ताओं के अनुकूल बनाने के लिए पहली बार एक सुगम मार्गदर्शिका जारी की है। यह मार्गदर्शिका केंद्र और राज्य सरकारों के मंत्रालयों और विभागों, नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, शिक्षाविदों, उद्योग हितधारकों और लोगों सहित उपयोगकर्ताओं के व्यापक वर्ग की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए बनाई गई है।

मंत्रालय ने कहा कि राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा प्रकाशित 'अपने सर्वेक्षण को जानें' दस्तावेज़, अधिक सूचित, जागरूक और सक्रिय डेटा उपयोगकर्ता समुदाय तैयार करने के लिये विभाग की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इस दस्तावेज़ में सर्वेक्षण के उत्तरदाताओं के लिए एक समर्पित अनुभाग भी शामिल है। इसमें क्षेत्र सर्वेक्षण के दौरान उत्पन्न होने वाले सामान्य प्रश्नों, चिंताओं और शंकाओं का समाधान किया गया है। यह दस्तावेज़ एक व्यापक और उपयोगकर्ता–अनुकूल मार्गदर्शिका के रूप में विकसित किया गया है ताकि असंगठित क्षेत्र के उद्यमों के वार्षिक सर्वेक्षण के उपयोगकर्ता मार्गदर्शिका को बेहतर ढंग से समझा जा सके।

गणतंत्र दिवस परेड के दौरान पहली बार सेना की पशु टुकड़ी कर्तव्य पथ पर करेगी मार्च

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

इस वर्ष गणतंत्र दिवस परेड के दौरान सेना की पशु टुकड़ी पहली बार कर्तव्य पथ पर मार्च करेगी। यह टुकड़ी देश के कुछ सबसे चुनौतीपूर्ण इलाकों में सैन्य अभियानों में जानवरों की महत्वपूर्ण भूमिका को प्रदर्शित करेगी। इस टुकड़ी में दो बैक्ट्रियन ऊंट, चार ज़ांस्कर खच्चर, चार शिकारी पक्षी, 10 भारतीय नस्ल के श्वान और वर्तमान में सेवा में मौजूद छह पारंपरिक सैन्य श्वान शामिल होंगे।जिन्हें अक्सर भारतीय सेना के मौन योद्धा कहा जाता है।

सेना के अनुसार, यह टुकड़ी अपने परिचालन तंत्र के भीतर परंपरा, नवाचार और आत्मनिर्भरता का मिश्रण प्रस्तुत करती है। टुकड़ी का नेतृत्व बैक्ट्रियन ऊंट करेंगे, जिन्हें हाल ही में लद्दाख के ठंडे रेगिस्तानों में अभियानों के लिए शामिल किया गया है। मेरठ के रिमाउंट एंड वेटरनरी–आरवीसी सेंटर और कॉलेज द्वारा प्रशिक्षित किए

गए ये श्वान आतंक विरोधी अभियानों, विस्फोटक और बारूदी सुरंगों का पता लगाने, सुरक्षा, आपदा प्रतिक्रिया और खोज तथा बचाव अभियानों में सैनिकों की सहायता करते हैं।

स्वस्थ और रोगमुक्त जीवन के लिए अपनाएं आयुर्वेदिक दिनचर्या

नई दिल्ली, 02 जनवरी।

मानव शरीर एक ऐसी मशीन की तरह कार्य करता है, जिसे सुचारू रूप से चलने के लिए समय–समय पर सर्विस और सही गुणवत्ता वाले ईंधन की आवश्यकता होती है। शरीर भी एक निश्चित लय यानी रिदम के अनुसार काम करता है। यदि यह लय संतुलित बनी रहे, तो बीमारियों का शरीर में प्रवेश कठिन हो जाता है और बढ़ती उम्र का असर भी देर से दिखाई देता है।

वैज्ञानिक भाषा में इस लय को 'सर्केडियन रिदम' कहा जाता है, जबकि आयुर्वेद में इसे 'दिनचर्या' के रूप में जाना जाता है। आयुर्वेदिक दिनचर्या का पालन कर शरीर को मजबूत, ऊर्जावान और रोगमुक्त रखा जा सकता है। आइए जानते हैं, आयुर्वेद में बताई गई इस विशेष दिनचर्या के बारे में।

आयुर्वेद के अनुसार दिन की शुरुआत ब्रह्म मुहूर्त में उठकर करनी चाहिए। शरीर से विषाक्त पदार्थ निकलने के बाद तांबे के बर्तन में रखा पानी पीना लाभकारी होता है। बालों और त्वचा के निखार के लिए नाभि में तेल की कुछ बूंदें डालें और आंखों में अंजन करें। इसके बाद हल्का व्यायाम और सैर करें, फिर अभ्यंग यानी तेल मालिश जरूर करें। अभ्यंग से शरीर में रक्त संचार बेहतर होता है और मांसपेशियों की थकान दूर होती है।

आयुर्वेद में आहार को अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। आहार केवल पेट भरने का साधन नहीं, बल्कि शरीर को ऊर्जा देने का प्रमुख स्रोत है। दोपहर का भोजन 12 बजे से 1 बजे के बीच करना चाहिए, क्योंकि इस समय जठराग्नि सबसे प्रबल होती है और भोजन आसानी से पच जाता है। रात का भोजन हल्का रखें और सूर्यास्त के बाद भोजन करने से बचें।

भोजन के बाद तुरंत बिस्तर पर लेटने के बजाय कुछ कदमों की हल्की सैर करनी चाहिए। यदि सैर संभव न हो, तो कुछ समय के लिए वज्रासन में बैठना लाभकारी होता है। यह आसन पाचन क्रिया को बेहतर बनाता है।

स्वस्थ जीवन के लिए नींद का सही समय और गुणवत्ता भी बेहद जरूरी है। नींद शरीर की मरम्मत का कार्य करती है। रात में गहरी नींद के लिए दूध के साथ त्रिफला या हल्दी का सेवन किया जा सकता है। इससे तनाव कम होता है और नींद बेहतर आती है। सोते समय बाईं करवट लेटना लाभकारी माना गया है, क्योंकि इससे रक्त संचार संतुलित रहता है और नींद अच्छी आती है।